पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 18, अंक 4/2017

राजस्थान हो रहा है जैविक कृषि की ओर अग्रसर - सीताराम भाले

खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। मद्देनजर अब राजस्थान लगातार जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण यहां की मिट्‌टी का परम्परागत रूप से जैविक खेती से जुड़ा होना है।

राजस्थान कृषि विभाग के आयुक्त विकास सीताराम भाले ने यह विचार 'कट्स' द्वारा 'ग्रीन एक्शन वीक' 2017 के तहत जयपुर में आयोजित 'सभी के लिए सतत सुरक्षित भोजन' पर परिचर्चा का उद्‌घाटन करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार अब जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है।

इसके लिए सरकार की पहल पर परम्परागत कृषि विकास योजना के रूप में 1150 कलस्टर विकसित किए गए हैं, जिसमें एक कलस्टर 50 हैक्टर का है। इसके साथ ही घरों में भी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से 'किचन गार्डन' के माध्यम से जैविक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान के निदेशक डॉ. शीतल प्रसाद शर्मा ने रासायनिक खेती के नकारात्मक प्रभावों को उजागर करते हुए कहा कि भारत में सभी किस्मों के बीज उपलब्ध हैं। इन्हें विकसित करने में कृषि अनुसंधान केन्द्रों को आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को यह जानना जरूरी है कि जो खाद्य सामग्री जैसे फल व सब्जियां अधिक तेज रंग एवं चमक वाली होती हैं, वह नुकसानदेह होती हैं। हमें उनका उपयोग करने से बचना चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि 'कट्स' द्वारा 'ग्रीन एक्शन वीक' परियोजना वर्ष 2010 से स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन के सहयोग से चलाई जा रही है। उन्होंने विभिन्न आंकड़ों और तथ्यों को सामने रखते हुए भारत में जैविक खेती को तेज गति से बढ़ाने, जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और सतत उपभोग की पैरवी की। इस अभियान के दौरान सौ किचन गार्डन विकसित किए गए हैं।

जयपुर जिले में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 97 प्रतिशत उपभोक्ता जैविक पदार्थों को खरीदने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बाजार में यह आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। 'कट्स' की परियोजना सहायक निमिषा गौड़ ने एक माह के अभियान के दौरान की गई गतिविधियों और इसके परिणामों पर प्रस्तुतिकरण दिया।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र का संचालन 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने किया। उन्होंने राजस्थान में जैविक खेती की वस्तुस्थिति और उसके बारे में लोगों की समझ पर विस्तार से जानकारी दी। तकनीकी सत्र में डॉ. बी.डी. यादव, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दुर्गापुरा ने देशी खाद के इस्तेमाल पर जोर देते हुए जैविक खाद तैयार करने की विधि बताई।

डॉ. गजेन्द्र शर्मा, कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि विभाग ने किचन गार्डन की तकनीक के बारे में प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि किस तरह थोड़े से प्रयासों से घर में ही ताजी सब्जियां उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उगाई जा सकती हैं। डॉ. ए.के. गुप्ता, डीन, एस.के.एन. एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज, जोबनेर ने मिलावट से बचने के लिए किचन गार्डन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 100 से भी अधिक किसानों, कृषि विशेषज्ञों, उपभोक्ता संस्थाओं और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अंक में...

- विफलता की ओर स्टार्टअप इंडिया 3
- पीएम की योजनाओं की भी अनदेखी 4
- रोजगार के बारे में नहीं है सटीक आंकड़ा 7
- करोड़ों लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर 9
- एक भी महिला समूह डिफाल्टर नहीं 10

बैंकिंग ठगी से बचाव जरूरी - जोईया

आपकी बैंक संबंधी कोई भी शिकायत हो तो संबंधित बैंक को लिखित में देकर उसकी प्राप्ति रसीद जरूर लें तथा शिकायत का समाधान नहीं होने पर बैंकिंग लोकपाल को अपील प्रस्तुत करें। खासतौर पर उपभोक्ताओं को बैंकिंग ठगी से सावधान रहना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 'कट्स' एवं सामाजिक विकास समिति धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में धौलपुर में आयोजित जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जगदीश प्रसाद जोईया सहायक जनरल मैनेजर भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बैंक खाताधारकों से कहा कि उन्हें आधुनिक तकनीक के माध्यम से बैंक लेन-देन को समझ कर व्यवहार में लाना चाहिए। अपनी बचत का सही निवेश कर आप अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। बैंक अधिकारी इसमें अपके लिए सहायक हैं।

कार्यक्रम में चीफ एलडीएम प्रेम सिंह ने खाताधारकों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि वे बैंक अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखें। बैंक द्वारा की गई किसी भी प्रकार की वसूली के बारे में जानकारी लेने का हक खाताधारकों को है।

भारतीय स्टेट बैंक धौलपुर के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि किसी भी बैंक द्वारा फोन करके खाते या एटीएम के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली जाती है। ऐसे फर्जी कॉल करने वालों से खाताधारकों को सावधान रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुनीश पी. कोठारी काउंसलर, दिशा ट्रस्ट जयपुर ने ऑनलाइन खरीद, फण्ड ट्रांसफर करने और लेन-देन में सावधानी बरतने आदि के बारे में जानकारी दी।

'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने संस्था की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा कार्यक्रम अधिकारी सत्यपाल सिंह ने प्रतिभागियों को इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा से अवगत कराया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा से अभय तिवारी, पीएनबी से के.के.शर्मा ने भी बैंकिंग सेवाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में करीब 70 से ज्यादा लोगों की सक्रिय भागीदारी रही।

जैविक उत्पादों का उपयोग समय की जरूरत-मेघवाल

जैविक कृषि एवं पशु उत्पाद का उपयोग हमारे स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पुरखों ने हमेशा जैविक उत्पादों का उपयोग किया और वे लम्बी आयु प्राप्त करते थे। वर्तमान में खान-पान के तौर-तरीकों में बदलाव से मानव जीवन में कई गंभीर बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है।

राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने यह विचार वेटरनरी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय और 'कट्स' के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कृषक एवं पशुपालकों की पशुपालन तकनीक, जैविक पशु उत्पादों का प्रमाणिकरण और उनके महत्व पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

उन्होंने किसानों और पशुपालकों को आह्वान किया कि वे जैविक उत्पादों की दी जा रही वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुसार कार्य करें। इससे उनकी आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी। प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता करते हुए वेटरनरी कॉलेज के अधिष्ठाता प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि जैविक पशु उत्पादों की तकनीकों और इनके उत्पादों का प्रमाणीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आपकी आय और जन स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेटरनरी विश्वविद्यालय में स्थापित विभाग जैविक पशुपालन तकनीकों के विकास और प्रशिक्षण का लाभ राज्य के कृषक व पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। कार्यक्रम में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने जैविक परियोजना की विस्तार से जानकारी देते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजुवास के वित्त नियंत्रक अरविन्द विश्नोई, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. एस.सी. गोस्वामी, कुलसचिव प्रो. हेमन्त दाधीच, राजुवास के जैविक पशुधन उत्पाद तकनीक केन्द्र के प्रमुख अन्वेषक डॉ. विजय विश्नोई के साथ-साथ अनेक कृषि व पशुपालन संबंधित विशेषज्ञों व विद्वानों ने किसानों और पशुपालकों को कई महत्वपूर्ण जानकारी देकर लाभान्वित किया। कार्यक्रम में राज्य के करीब 100 से भी अधिक किसानों व पशुपालकों ने भाग लिया।

मनरेगा योजना का हाल बेहाल

अजमेर के गांव जटिया पीतावास की पुष्पा देवी के मनरेगा के चार हजार से ज्यादा रुपए पिछले छह महीने से अटके हुए हैं। उन्हें काम के बाद मजदूरी नहीं मिल रही। यह दर्द सिर्फ पुष्पा का ही नहीं प्रदेश में देरी से भुगतान के मामले में मनरेगा मजदूरी के 140 करोड़ रुपए अटके हुए हैं।

इतना ही नहीं हर परिवार को साल में 100 दिन काम देने की इस योजना में इस साल अब तक सिर्फ 12535 परिवारों यानी 13 फीसदी लोगों को ही 100 दिन काम मिला है। इस साल सरकार योजना का 97 फीसदी पैसा खर्च कर चुकी है। जबकि इस साल के कामों में से 99 फीसदी से ज्यादा काम अधूरे पड़े हैं। गौरतलब यह है कि चौंकाने वाली इन खबरों पर सरकार ने भी मौन साध रखा है। *(दै.भा., 09.10.17)*

कंपनियों ने कम दिखाया रेवेन्यू

देश की पांच टेलीकॉम कंपनियों ने अपना रेवेन्यू 14,814 करोड़ रुपए कम दिखाया, जिससे सरकार को 2,579 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार के ऑडिटर सीएजी (कैग) द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में यह बात उजागर की गई है। रेवेन्यू कम दिखाने वाली कंपनियों में टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर, वीडियोकॉन, क्वाड्रेंट और रिलायंस जियो शामिल हैं।

कैग के मुताबिक कंपनियों ने रेवेन्यू 14,813.97 करोड़ रुपए कम दिखाए। इससे सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज में 1,526.7 करोड़ रुपए कम मिले। इस पर जुर्माना जोड़ा जाए तो वह मार्च 2016 तक 1,052.13 करोड़ रुपए बनता है। कंपनियां हर साल जो लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज देती है वह उनके रेवेन्यू से जुड़ा होता है। *(दै.भा., 20.12.17)*

प्रधानमंत्री आवास योजना बेपटरी

सरकार के नाराजगी जाहिर करने के बावजूद प्रदेश में ग्रामीण विकास महकमा गरीबों के लिए आवास बनाने में निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे हैं। जबकि राज्य सरकार ने सभी जिलों को पिछले वर्ष के बकाया आवासों को अक्टूबर माह तक पूरा करने के निर्देश जारी किए थे।

बावजूद इसके सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 में निर्धारित 2.50 लाख आवासों में से अब तक सिर्फ 45 हजार 273 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं, जो लक्ष्यों की तुलना में मात्र 18 प्रतिशत है। गौरतलब यह भी है कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 का 2.23 लाख आवास बनाने का लक्ष्य पूरा बकाया है। *(रा.प., 01.11.17)*

विफलता की ओर स्टार्टअप इंडिया इनिशियेटिव...

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल शुरू किए गए महत्वाकांक्षी 'स्टार्टअप इंडिया इनिशियेटिव' केन्द्र की कई दूसरी योजनाओं की तरह विफल साबित हो रहा है। ये इनिशियेटिव चार साल तक हर साल स्टार्टअप्स को 2500 करोड़ रुपए की पूंजी मुहैया कराने के लिए शुरू हुआ था, जबकि दो साल बीत जाने के बाद भी इसके जरिये 75 स्टार्टअप्स को कुल 337 करोड़ रुपए की पूंजी ही मिली है।

राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, सिडबी ने 2015-16 में 500 करोड़ और 2016-17 में 100 करोड़ रुपए 17 एआईएफ को जारी किए। इसमें से भी एआईएफ ने 337 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही 75 स्टार्टअप्स को पैसा देने में किया। अब तक 5350 स्टार्टअप्स को देश में मान्यता दी जा चुकी है, जिसमें 40 हजार से ज्यादा कर्मी हैं। *(रा.प., 27.12.17)*

पर्यावरण सुधार पर नहीं हुआ खर्च

राज्य के खान क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार के साथ विकास कार्यों को लेकर करीब 1100 करोड़ रुपए राज्य सरकार एकत्रित कर चुकी है। लेकिन इस बजट में से विकास कार्यों पर अब तक महज 96 लाख रुपए भी खर्च नहीं हो सके। जिलों में कार्यों के निर्णय लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट गठित हुए, लेकिन इनमें राजनीतिक लोग ज्यादा होने के कारण खींचतान मची हुई है।

इनका गठन पिछले साल ही हो गया, पिछले वित्त वर्ष में खातों में 715 करोड़ का बजट भी जुटा लिया गया लेकिन सरकार काम नहीं करा सकी। अब सरकार ने सभी जिलों में 4548 कार्य कराने का निर्णय किया है, लेकिन अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से काम शुरू नहीं हो सके हैं। *(रा.प., 26.11.17)*

गोदामों में सड़ गया 7600 टन खाद

सहकारिता विभाग द्वारा राजफैड कोटा के माध्यम से करीब एक साल पहले अग्रिम भण्डारण योजना के तहत रखा गया 7600 टन यूरिया व डीएसपी खाद सड़ कर खराब हो गया। इसे राजफैड ने गोदामों से निकाल कर संभाग की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बेचने का दबाव बनाकर भिजवा दिया।

अब यह खाद संभाग की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों में पड़ा है। गोदामों में रखे इस खाद के ढेले बन गए। ढेले बने होने से इसे किसानों ने खरीदने से मना कर दिया है। *(रा.प., 30.10.17)*

संपत्ति का ब्यौरा देना भूले मंत्री

वर्ष 2010 में केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय व राज्यों के मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल 31 अगस्त तक देना अनिवार्य किया था। लेकिन राज्य में अपनी सरकार के चार साल पूरे होने का जश्न मना रहे मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना भूल गए हैं।

महज दो मंत्रियों (उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी और राजस्व राज्य मंत्री अमराराम) ने ही अपनी संपत्ति और कारोबार की जानकारी दी है। शेष मंत्रियों सहित कई आईएएस अफसर भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं। कई मंत्रियों ने तो 2014-15 के बाद संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। *(रा.प., 08.12.17)*

बीमा कंपनियां हो रही मालामाल

किसानों का फसल बीमा करने वाली कंपनियां मालामाल हो रही हैं। कंपनियों ने वर्ष 2016-17 में रबी तथा खरीफ सीजन में किसानों से प्रीमियम के तौर पर 2406 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जबकि बड़े पैमाने पर फसल खराब होने के बावजूद 1066 करोड़ रुपए का क्लेम स्वीकृत किया गया ।

किसान हताश है, लेकिन कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया है। इसके अलावा सरकार की कई योजनाओं में कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। सरकार बनाते समय किसानों से लुभावने वादे करने वाली सरकार केवल तमाशा देखती रही। *(रा.प., 11.12.17)*

पीएम की योजनाओं की भी अनदेखी

सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अटल पेंशन, जन-धन और जीवन ज्योति जैसी कई योजनाओं का एलान किया था। इन्हें शुरू करने का मकसद लोगों के भविष्य को सुरक्षित करना था। लेकिन योजनाएं शुरू करने से पहले जरूरी तैयारियों और उन्हें सफल बनाने के लिए उठाने वाले कदमों में भारी लापरवाही दिखी।

ये खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पसंदीदा योजनाएं हैं। लेकिन कुछ योजनाओं में महज एक प्रतिशत रकम का ही उपयोग हुआ है तो कुछ में एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जैसे अटल पेंशन योजना में 2016-17 में 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए उसमें से 29 करोड़ ही इस्तेमाल हुआ। आम आदमी बीमा योजना और वरिष्ठ बीमा योजना का भी यही हश्र रहा है। योजनाओं के बारे में संसदीय समिति ने भी केन्द्र के अधिकारियों को मेहनत करने की नसीयत दी है। *(रा.प., 26.12.17)*

टैंकर पहुंचे नहीं, उठा लिया भुगतान

जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर स्कूटर, बाइक व कार के नंबरों से चले पानी के फर्जी टैंकरों के बिलों का भुगतान कर दिया। विभाग की इंटरनल ऑडिट के साथ ही महालेखाकार (एजी) ऑडिट टीम ने मामला पकड़ा भी लेकिन विभाग के आला अफसरों ने फाइल को दबाए रखा।

यह केवल जयपुर जिले के आठ डिविजनों में बंटे एक डिविजन का ही नहीं नागौर सहित अन्य शहरों में टैंकर सप्लाई में दो करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला सामने आया है। इसमें से करीब 50 लाख रुपए का भुगतान भी हो चुका है। अभी मामले में एजी और इंटरनल ऑडिट टीम की जांच जारी है जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। *(दै.भा., 10.12.17)*

राजकोष को लगाया करोड़ों का चूना

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी आवासों का निर्माण नहीं करने पर राजकोष को 7.78 करोड़ रुपए का चूना लगा। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में बीपीएल परिवारों को नए आवास निर्माण के लिए वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरु की गई।

इस योजना में लाभार्थी को 50 व 45 हजार रुपए की वित्तीय सहायता का भुगतान तीन किश्तों में करना था। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वर्ष 2011-12 व 2012-13 में 3182 आवासों के लिए 7.78 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन इन आवासों का निर्माण चार साल तक भी नहीं हुआ। राशि वसूल नहीं होने पर एफआईआर दर्ज करानी थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। *(दै.न., 30.10.17)*

खातों में पड़ा रहा विधायकों का पैसा

विधायक निधि कोष का पैसा जिला परिषदें विकास कार्यों पर खर्च ही नहीं कर पा रही हैं। आवंटित राशि में से 1093 करोड़ रुपए अब भी जिला परिषदों के बैंक खातों में पड़ा है। यह आवंटित राशि का 60.73 फीसदी है। विधायक निधि कोष की 20 फीसदी राशि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में होनी चाहिए, वह भी तय मापदण्डों के मुताबिक खर्च नहीं हो रही।

यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विधानसभा के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन में हुआ है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के पांच जिलों बीकानेर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद के परीक्षण में सामने आया कि पांच वर्षों (2011 से 2016) के दौरान मात्र 21.05 फीसदी राशि का ही उपयोग हुआ। यहां कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं। *(रा.प. एवं दै.भा., 25.10.17)*

हजारों क्विंटल गेहूं पड़ा रहा गोदामों में

प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से अक्टूबर 2013 से पूर्व संचालित विभिन्न योजनाओं में आवंटित गेहूं अंधेरगर्दी के चलते बिना वितरित हुए गोदामों में पड़ा रह गया। अब चार साल बाद सरकार को इसकी याद आई तो यह जांचने के लिए कमेटी बनाई गई कि गेहूं इंसान और पशुओं के खाने लायक भी है या नहीं।

यह गेहूं राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व संचालित योजनाओं का है और यह थोक विक्रेताओं के पास स्टॉक में है। अब स्टॉक में पड़े गेहूं की पड़ताल करने की कवायद शुरू हुई है। इसके लिए जिला स्तर पर पांच सदस्यों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। *(रा.प., 25.10.17)*

महंगा पेपर खरीदकर लगाई चपत

केन्द्र सरकार की ओर से निर्धारित दरों के खिलाफ जाकर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल पिछले 2 साल से पंजाब की चहेती फर्मों से महंगा पेपर बिना टेंडर के खरीद रहा है।

केन्द्र सरकार जो पेपर वर्षों तक सुरक्षित रखा जाने वाला गजट छपवाने के लिए भी नहीं खरीदती, उसे किताबों के लिए खरीदकर मण्डल सरकारी खजाने को अब तक 21 करोड़ रुपए की चपत लगा चुका है। मण्डल ने इस कागज का इस्तेमाल स्कूलों में निःशुल्क दी जाने वाली किताबों के छापने में किया, जो सिलेबस में बदलाव के कारण कम ही समय तक काम आती है। *(रा-प., 25.12.17)*

रिश्वतखोरों ने बिगाड़ा पुलिस का गणित

पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए लागू की गई कार्य मूल्यांकन योजना में लगभग हर जिला पुलिस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत रिश्वतखोर अफसर और कर्मचारी बन गए हैं। राज्य के 40 पुलिस जिलों में इस साल जनवरी से अब तक 74 पुलिसकर्मी रिश्वत के मामलों में ट्रैप हो चुके हैं।

इस कार्रवाई के कारण स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) ने कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में 3700 अंक काटे हैं। फिलहाल आकलन और विश्लेषण के लिए इस्तेमाल हो रही कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट पर अगले साल से कार्रवाई भी शुरू होना तय है। यानी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पुलिसकर्मियों वाले जिलों के लिए मुश्किल बढेगी।

(दै.भा., 21.12.17)

भ्रष्टाचार व गरीबी मुक्त होगा भारत

सरकार को सलाह देने वाली संस्था नीति आयोग का कहना है कि 2022 तक भारत भ्रष्टाचार, गरीबी,जातिवाद और सांप्रदायिकता मुक्त न्यू इंडिया होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पिछले महीने राज्यपालों के सम्मेलन में 'न्यू इंडिया एट 2022' दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि अगर भारत 8 प्रतिशत की वृद्धि दर से आगे बढ़ना जारी रखता है तो 2047 तक विश्व की टॉप शीर्ष तीन अर्थव्यवस्था में शामिल होगा।

न्यू इंडिया एट 2022 दस्तावेज में अनुमान किया गया है कि 2022 तक भारत पूरी तरह से कुपोषण मुक्त हो जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित सभी गांव 2022 तक आदर्श गांव का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

(रा.प. एवं दै.न., 05.11.17)

अब मंत्रियों से भी मांग सकेंगे सूचना

राजस्थान सूचना आयोग ने प्रदेश के मंत्रियों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम दायरे में माना है। आयोग ने मंत्रियों के कार्यालय को लोक प्राधिकरण मानते हुए स्वतः सार्वजनिक की जाने वाली करीब डेढ़ दर्जन सूचनाओं को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस आदेश के बाद अब मंत्रियों के कार्यालय से सीधे सूचना मांगी जा सकेगी। मुख्य सचिव को एक माह में लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त कराने को कहा है। सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने गौरीशंकर मालू की अपील पर यह आदेश दिया। आयोग ने हैरानी जताई कि जब मुख्यमंत्री का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में है, तो मंत्रियों के कार्यालयों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है?

(रा.प.एवं दै.न., 03.10.17)

भ्रष्टाचार है प्रजातंत्र के लिए खतरा

कुशासन और भ्रष्टाचार साथ-साथ चलता है। हमें भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना है तो सुशासन की अवधारणा को लागू करना होगा। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को दूर करने का सशक्त माध्यम है।

केन्द्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने यह विचार राजस्थान पुलिस अकादमी व ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के तत्वावधान में आरटीआई पर आयोजित व्याख्यान में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह विश्व का चौथा सबसे सशक्त कानून है और कार्य में पारदर्शिता लाने का कारगर उपाय है। *(रा.प., 09.11.17)*

स्विट्ज़रलैंड बताएगा काला धन

काले धन के खिलाफ सख्त कदम के तहत भारत ने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक बड़ा करार किया है। इसके तहत अब एक जनवरी से टैक्स से संबंधित सूचनाएं अपने आप ही साझा हो जाएगी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह जानकारी दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में संसदीय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद और साझा समझौते पर दस्तखत हुए हैं। इसमें दोनों देशों के बीच एक जनवरी 2018 से सूचनाएं खुद-ब-खुद साझा हो सकेगी। आयकर विभाग ने बताया कि सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चन्द्रा और भारत में स्विस राजदूत एंड्रियास बेयम के बीच इस करार पर दस्तखत हुए हैं। *(रा.प., 22.12.17)*

सब्सिडी में भ्रष्टाचार कम हुआ

इन्फोसिस चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने कहा है कि आधार से सब्सिडी का गलत इस्तेमाल रुका है, और सरकार को पिछले तीन सालों में 58,500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सौ करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आधार बन चुका है और करीब 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते आधार से जुड़ चुके हैं। सरकार इसके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं से संबंधित लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर चुकी है।

जह जानकारी 'विकास के लिए डिजिकल इकोनॉमी' विषय पर वर्ल्ड बैंक की परिचर्चा में देते हुए उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश हैं जहां 100 करोड़ लोग आधार के जरिए अपने मोबाइल फोन पर कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन की लागत घटने के साथ ज्यादा लोग इसे अपनाएंगे।

(दै.भा., 14.10.17)

जब्त होने जगी है बेनामी संपत्तियां

आयकर विभाग अब तक 1,833 करोड़ रूपए की बेनामी संपत्तियों को जब्त कर चुका है। यह जानकारी देते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चन्द्रा ने कहा कि विभाग बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखेगा।

उन्होंने कहा कि हम सभी स्थानों से ऐसी संपत्तियों से संबंधित जानकारी हासिल करने में जुटे हैं और बेनामी संपत्ति की पहचान करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने पिछले साल एक नवंबर से नए बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस कानून में अधिकतम सात साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

(दै.न., 08.11.17)

अपना काम कराने को देते हैं रिश्वत

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा हाल ही किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 45 फीसदी उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि अपना काम पूरा कराने के लिए पिछले 12 महीनों में उन्होंने कम से कम एक बार रिश्वत दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने यह सर्वेक्षण सोशल नेटवर्क लोकल सर्कल के सहयोग से किया।

सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 34,696 भागीदारों को शामिल किया गया था। उनसे 'पिछले 12 महीनों में भ्रष्टाचार के स्तर में बदलाव' के बारे में वे क्या समझ रखते हैं, इसकी जानकारी ली गई। जिनमें से 11 राज्यों के 12,964 (37 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि इस अवधि के दौरान भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। जबकि 45 प्रतिशत का मानना था कि यह स्थिर बना रहा। मात्र 14 फीसदी का कहना रहा कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। करीब 4 फीसदी उत्तरदाताओं ने जवाब देने में असमर्थता जाहिर की। समानान्तर सर्वेक्षणों में करीब 51 फीसदी भागीदारों ने जवाब दिया कि उनके राज्य में पिछले साल भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

(न.नु., 12.12.17)

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
बांसवाड़ा	खगेश दोसी	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बांसवाड़ा	1,00,000	रा.प. एवं दै.न., 05.10.17
राजसमंद	धर्मेन्द्र सिंह	कांस्टेबल, कांकरोली थाना, राजसमंद	10,000	दै.न., 17.10.17
जयपुर	नवीन कुमार	कांस्टेबल, सेज थाना, जयपुर	6,900	दै.भा., 26.10.17
जयपुर	डॉ. बी.एल मीणा	डॉक्टर, सेटेलाइट अस्पताल, सेठी कॉलोनी	10,000	रा.प. एवं दै.भा., 28.10.17
सीकर	महेश कुमार पवन यादव	हैड कांस्टेबल, थोई थाना, सीकर दलाल	10,000	रा.प., 28.10.17
बीकानेर	महावीर प्रसाद शर्मा	पंचायत प्रसार अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति	1,00,000	दै.न., 29.10.17
श्रीगंगानगर	शीश राम	प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल	21,000	रा.प., 08.11.17
झुंझुनूं	रविन्द्र कुमार	कनिष्ट अभियंता, विद्युत वितरण निगम, बुहाना	8,000	रा.प. एवं दै.न., 08.11.17
कोटा	नलिन भट्ट सुरेश सैनी	इंस्पेक्टर, भविष्य निधि विभाग इंस्पेक्टर, भविष्य निधि विभाग	25,000	दै.भा., 09.11.17
बाड़मेर	देवेन्द्र कविया	थानाधिकारी, पचपटरा थाना, बाड़मेर	50,000	दै.न., 19.11.17
उदयपुर	विपिन कुमार बापना गोपाल पटेल	एईएन, भूजल एवं संरक्षण विभाग जेईएन, भूजल एवं संरक्षण विभाग	2,04,000	दै.न., 21.11.17
भरतपुर	राकेश यादव प्रताप उर्फ टिंकू यादव	एसएचओ, कामां थाना, भरतपुर दलाल, अंबेडकर चौराहा कामां निवासी	40,000	रा.प. एवं दै.भा., 29.11.17
जयपुर	कुलदीप गोदारा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	50,000	रा.प. एवं दै.भा., 01.12.17
उदयपुर	कुसुम तम्बोली	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हींता शाखा	25,000	रा.प. एवं दै.न., 01.12.17
अलवर	भगवान सहाय यादव	नायब तहसीलदार, नारायणपुरा, थानागाजी	1,40,000	दै.न. एवं रा.प., 01.12.17
जयपुर	गीता चौधरी	महिला सब इंस्पेक्टर, महिला थाना (ईस्ट)	70,000	दै.भा. एवं रा.प., 13.12.17
चित्तौड़गढ़	सुनील कुमार सैनी	वन रक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय, बेगूं	40,000	रा.प. एवं दै.न., 15.12.17
हनुमानगढ़	जगदीश सिंह	सहायक उप निरीक्षक, रावतसर पुलिस थाना	60,000	रा.प. एवं दै.भा., 23.12.17
बीकानेर	रूपेश कुमार	जेईएन, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	10,000	रा.प., 25.12.17द्ध
जयपुर	हरकेश मीणा	सब डिविजनल इंजीनियर, बीएसएनएल	70,000	दै.भा., 30.12.17

ग्राहक बनेंगे ताकतवर-मोदी

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उनके हितों से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार नया कानून ला रही है। जिससे उनके अधिकारों को और मजबूत किया जा सकेगा और उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर गुमराह करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के यहां आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने के बाद केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

सम्मेलन में 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप महता ने कहा कि हम 'कट्स' में लंबे समय से इसी विषय पर काम कर रहे हैं। यह चिंतन का विषय है कि भारतीय प्रशासनिक बंधुओं ने अपने सेवानिवृत्त साथियों की पुनर्स्थापना के लिए फिर से एक नया स्थान चुन लिया है। ऐसा हुआ तो यह 'उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' को निष्प्रभावी करने के लिए काफी होगा।

देश में अब आयकर सुधार की बारी

वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के बाद मोदी सरकार ने दूसरे बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने 56 साल पुरानी आयकर की टैक्स व्यवस्था को देश की वर्तमान जरूरतों के अनुसार बदलने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा।

समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। समिति से देश की वर्तमान जरूरतों के अनुसार नए विधेयक का मसौदा बनाने को कहा गया है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार की मंशा जल्द ही एक सरल और साफ कानून लाने की है।

समिति की रिपोर्ट अगले साल मई तक आने की उम्मीद है। देश में होने वाले 2019 के आम चुनावों के पहले अंतरिम बजट में इसमें बदलाव की रूपरेखा पेश की जा सकती है। *(रा.प., 23.11.17)*

डाक विभाग बनाएगा आधार कार्ड

आम आदमी के लिए जरूरी बन चुके आधार कार्ड अब डाकघर के जरिए ही बनेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर वित्त मंत्रालय ने देशभर में डाकघर विभाग के 14 हजार 30 डाकघरों में आधार नामांकन व अपडेट सेंटर खोलने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है।

बजट मिलने के बाद डाक विभाग ने देशभर में आधार केंद्र खोलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के 610 डाकघरों में आधार कार्ड बनवाने तथा अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। *(रा.प., 28.10.17)*

मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं

राज्य सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले चार सालों के दौरान प्रदेश के विकास हेतु किए गए कामों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

इनमें सरकारी अस्पतालों में हृदय रोगियों को मुफ्त एंजियोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने, किसानों को साढ़े पांच फीसदी की दर से सस्ता कर्ज देने, सड़क हादसे में घायलों का 48 घंटे तक फ्री इलाज करने, सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 साल करने, शहीद सैनिकों के एक परिजन को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने जैसी कई घोषणाएं शामिल है। *(दै.भा.एवं दै.न., 14.12.17)*

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना...

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं द्वारा पंजीयन, जांच, प्रसव व बच्चे का जन्म पंजीकरण करवाने पर अब सरकार पांच हजार रुपए देगी। नये साल की एक जनवरी से इस योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत महिलाओं को यह लाभ पहले जीवित बच्चे पर ही मिलेगा।

महिलाएं केवल एक बार ही योजना का लाभ ले पाएंगी। तीन किस्तों में मिलने वाली इस राशि के लिए समेकित बाल विकास निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आवेदन करना होगा। *(रा.प. 15.12.17)*

किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न तरीकों से मदद के कार्य शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे कृषि क्षेत्र को लाभ होगा और उस क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं बढ़ेंगी।

कृषि में उपयोगी खाद और बीज की लागत कम करने के साथ ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, बिजली, आवास और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में सुधार करने की कोशिश कर रही है, ताकि इससे किसानों को मदद मिल सके। साथ ही उनकी मदद के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी कवायद की जा रही है। *(दै.न., 17.12.17)*

रोजगार के बारे में नहीं है सटीक आंकड़ा

नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने कहा है कि देश में रोजगार के बारे में कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। परिषद की पहली औपचारिक बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हमारे पास रोजगार को लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है।

उन्होंने कहा देश में जो भी आंकड़े हैं वह परिवारों के बीच किए गए सर्वे पर आधारित हैं। फिलहाल जो रोजगार पर आंकड़े उपलब्ध होते हैं, वह समय पर नहीं आते और जो आंकड़े आते हैं वह संगठित क्षेत्र तक सीमित होते हैं। उन्होंने कहा परिषद की पहली बैठक में 10 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें आर्थिक वृद्धि, रोजगार एवं रोजगार सृजन सबसे ऊपर है। देबराय ने कहा, परिषद अपनी अगली बैठक में रोजगार के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। *(न.नु., 12.10.17)*

उपकरण लाएंगे बिजली बिल में कमी

सरकार कम बिजली खपत करने वाले उपकरणों को और दक्ष बनाने के लिए कदम उठा रही है। अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के मुकाबले कम से कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत करेंगे। कुल मिलाकर इससे आपके बिजली बिल में खासी कमी आएगी।

बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाला ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (बीईई) स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के तहत संबंधित उपकरणों पर बिजली बचत के लगाए जाने वाले सितारे (स्टार लेबलिंग) की तरह अति दक्ष उपकरणों के लिए विनिर्माता कंपनियों को अलग निशान (लेबल) उपलब्ध कराएगा। *(न.नु., 24.10.17)*

हर माह चुकाना होगा बिजली बिल

अब बिजली उपभोक्ताओं को अगले साल अप्रेल से बिजली का बिल हर महीने चुकाना होगा। विद्युत नियामक आयोग ने करीब नौ महीने पहले दर्ज प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका पर यह निर्देश दिए हैं। अभी बिजली उपभोक्ताओं को दो माह में एक बार बिजली का बिल चुकाना होता है।

इस बार याचिका में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव नहीं थे, ऐसे में बिजली उपाभोक्ताओं की जेब पर कोई भार नही बढ़ेगा। दूसरी ओर दो माह की बजाय एक माह में बिल गणना होने से टैरिफ के अनुसार छोटे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। चूंकि एक माह के उपभोग में उपभोक्ता छोटी श्रेणी के स्लैब में आता है और उसके लिए बिजली की दर भी कम होती है। उपभोक्ता अगर निश्चित तिथि से दस दिन पहले बिल जमा कराएगा तो उसे 0.35 फीसदी छूट दी जाएगी। *(दै.भा., 04.11.17)*

बिजली से वंचित चार करोड़ परिवार

देश के चार करोड़ से ज्यादा परिवार अभी भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इनमें से एक चौथाई से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। बिजली मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर 2017 तक चार करोड़ पांच लाख 74 हजार 727 घरों तक बिजली नहीं पहुंची है। इनमें से एक करोड़ 45 लाख 80 हजार 929 परिवार उत्तरप्रदेश के हैं। पंजाब, तमिलनाडू और गोवा के शत-प्रतिशत घर रोशन हो चुके हैं।

असम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश ओडिसा और राजस्थान में बिना बिजली अंधेरे में रहने वाले परिवारों की संख्या लाखों में हैं। राजस्थान के 19 लाख 50 हजार 545 घरों में बिजली नहीं पहुंची है। *(दै.न., 25.12.17)*

रसोई में हो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्टार्टअप इकाइयों को सलाह दी है कि वे रसोई के लिए स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए सौर ऊर्जा बाजार में संभावनाएं तलाशें।

उन्होंने इसे एक विशाल बाजार बताते हुए कहा कि पिछले 35 सालों में सरकारों ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर कुल मिलाकर 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। जबकि उनकी सरकार ने आने के बाद इस मद पर करीब 11 हजार करोड़ रुपए लगाए हैं। उन्होंनें कहा कि भारत में 2030 तक 40 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्त्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और सरकार ने 2022 तक इन स्त्रोतों से एक लाख 75 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है। *(न.नु., 31.10.17)*

सौर और पवन ऊर्जा से होगा औद्योगिक विकास

केंद्र सरकार सौर और पवन ऊर्जा को बिजली का प्रमुख सोर्स बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है। इससे बिजली सस्ती होगी तो उद्योगों के उत्पादों की कीमत भी कम होगी और अन्तरराष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में ठहर सकेंगे।

गुजरात में पवन ऊर्जा निकासी में निर्धारित दर से भी कम दर का आना स्वागत योग्य कदम है। इसी को देखते हुए अब सरकार हमारे राज्य में भी सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की दिशा में सकारात्मक सहयोग करे, ताकि पूंजी निवेशक इसका लाभ उठा सकें और राज्य में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित हो सकें। इसके लिए सरकार बंजर भूमि और पहाड़ों व पठारों की जमीन का उपयोग आसानी से कर सकती है। *(न.नु., 27.12.17)*

सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने को नई स्कीम

सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार 11,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने पर विचार कर रही है। इसकी घोषणा एक फरवरी को बजट में की जा सकती है। निवेश राशि के 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। यानी 1,000 करोड़ रुपए के निवेश पर अधिकतम 300 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी।

सब्सिडी नहीं लेने वाली और पहले से सोलर आइटम बना रही यूनिट्स को वेफर, सेल व पॉलिसिलिकॉन के उत्पादन के लिए सरकारी बैंकों से 3 प्रतिशत कम ब्याज दरों पर कर्ज दिए जाएंगे। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक इन प्रस्तावों पर सभी पक्षों से राय मांगी है। अगले माह इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। *(दै.भा., 19.12.17)*

सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन

शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों को भी अब मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेंगे। साथ ही बिजली से महरूम परिवारों के घर भी मात्र 500 रुपए में रोशन हो सकेंगे। यह संभव होगा केन्द्र सरकार की सभी को बिजली उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई सौभाग्य योजना से।

विद्युत वितरण निगम ने इस योजना के तहत ऐसे परिवारों की सूचियां तैयार करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे में नगर निगम, परिषद, पालिकाओं एवं जनप्रतिनिधियों की मदद भी ली जाएगी। योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले पात्र गरीब परिवारों को सर्वे के पश्चात घरेलू बिजली कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे।

(दै.न., 12.11.17)

करोड़ों लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर

भारत के 21 राज्यों के 153 जिलों में रहने वाले करीब 24 करोड़ लोग खतरनाक आर्सेनिक स्तर वाला पानी पीते हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा असम की 65 प्रतिशत आबादी आर्सेनिक दूषित पानी पीती है। जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार में यह आंकड़े 44 और 60 फीसदी है।

लोकसभा में उठे एक सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक, आबादी के लिहाज से सबसे अधिक प्रभावी राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां सात करोड़ आबादी जहरीला पानी पीने को मजबूर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लंबे समय तक आर्सेनिक युक्त पानी पीने से आर्सेनिकोसिस हो सकता है। इसके अलावा त्वचा का कैंसर, गाल ब्लैडर, किडनी, डायबिटीज, हाईपरटेंशन या फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो सकती है। *(रा.प., 25.12.17)*

सूखी धरती से भी खींच रहे पानी!

प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर का भूजल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। जितना पानी धरती में नहीं जा रहा, उससे कई गुना ज्यादा पानी खींचा जा रहा है। शहर का औसतन जल स्तर 250 फीट है, लेकिन कई क्षेत्रों में यह स्तर 350 फीट पर चला गया है।

मानसून सत्र में महज 5 से 10 प्रतिशत पानी का संरक्षण किया जा रहा है, जबकि इससे पांच गुना अधिक पानी का दोहन हो रहा है। ज्यादा दोहन होने से कई इलाकों में तो पानी 400 फीट पर भी नसीब नहीं है। जल संरक्षण के प्रति न तो भूजल विभाग ना ही जेडीए गंभीरता दिखा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में वर्षा जल का उचित प्रबंधन, संचयन और पुनर्भरण जरूरी है। अतःघर-घर में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने पर जोर देना चाहिए। *(रा.प., 17.10.17)*

कम बारिश से पेयजल संकट के आसार

प्रदेश में कम बारिश के चलते 14 जिलों में अभी भी पेयजल संकट की आशंका बनी हुई है। जलदाय विभाग द्वारा गर्मियों में पेयजल की डिमांड को देखते हुए इन जिलों के अभी से प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि समय पर वित्तीय स्वीकृति जारी कर लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सके।

जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जिन जिलों में पानी की समस्या होने की स्थिति सामने आई है, उनमें किस स्त्रोत के जरिए पानी मुहैया कराया जाएगा इसके लिए भी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है कि मार्च से पहले ही सभी तरह की स्वीकृति ले ली जाए। उन्होंने बताया कि पिछले चार साल में 17 हजार 322 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। *(दै.न., 06.12.17)*

ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा पेयजल

प्रदेश में अब एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में भी घर-घर पानी पहुंचाया जाएगा। सीमांत क्षेत्रों के गांवों के लिए तीन हजार की आबादी के नियम में शिथिलता देते हुए यह नीतिगत फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की 10 हजार ग्राम पंचायतों तक सतही स्त्रोतों से मीठा जल पहुंचाने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए लागत की परियोजना के लिए केन्द्र सरकार से मदद का आग्रह किया है। राजे ने बताया कि सतही जल स्त्रोतों से करीब 92 प्रतिशत और भूजल स्त्रोतों से मात्र 8 प्रतिशत निर्भरता रखने के लिए राज्य के जल संसाधन एवं पेयजल विभाग ने संयुक्त विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। दोनों विभाग पीडीकोर एजेंसी तथा केन्द्र सरकार की सहायता से इस योजना को क्रियान्वित करेंगे *(दै.न., 26.11.17)*

प्रदेश के 14 जिलों में पेयजल चुनौती

प्रदेश के अधिकतर जिलों में 20 से 60 प्रतिशत कम बरसात होने से पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है। करीब 14 जिलों के 831 बांधों में से महज 241 बांधों में ही पर्याप्त मात्रा में पानी है, जबकि 285 बांध आंशिक रूप से भरे हुए हैं और 305 बांध पूरी तरह से सूखे पड़े हैं।

विभागीय आकलन के अनुसार गत वर्ष की तुलना में इस बार बांधों में 16 प्रतिशत बारिश का पानी कम आया है, जिसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जयपुर संभाग के बांधों में कुल क्षमता का 33 प्रतिशत पानी ही है, जिससे कई क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। कम बरसात के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई है, जिसके कारण हैंडपंप और ट्यूबवैल भी सूख रहे हैं। *(दै.न., 27.12.17)*

पेयजल टैंकरों पर करोड़ों का खर्च

राजधानी जयपुर शहर में अधिकतर क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने के बाद भी टैंकरों से पेयजल सप्लाई पर हर महीने करीब सवा करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड को अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक के लिए 770.91 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

पॉलिसी प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार शहर के कच्ची बस्ती के साथ ही बाहरी इलाकों में पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसमें पानी टैंकरों के जरिए ही मुहैया कराया जा रहा है जो मार्च 2018 तक जारी रहेगा। *(दै.न., 27.10.17)*

जल संसाधनः एक जुबानी जमा खर्च

सरकार के चार साल के जश्न में अपने विभाग की उपलब्धियां बताने में कोई भी विभाग पीछे नहीं हैं। जल संसाधन मंत्री डॉ. राम प्रताप ने दावा किया है कि चार साल में उनके महकमे ने 11 हजार 930 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की है।

दूसरी तरफ मंत्री के दावों की जमीनी हकीकत सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही साबित हुई। जिन परियोजनाओं की उन्होंने उपलब्धियां बताई वे चार सालों से सिर्फ कागजों में है। ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो सालों से अंतरराज्यीय जल विवाद में फंसे हुए हैं। कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिन पर काम डीपीआर से आगे बढ़ा ही नहीं। परवन और धौलपुर परियोजना के काम भी अभी प्रस्तावित ही है। *(दै.भा., 12.12.17)*

महिला सुरक्षा में राजस्थान पिछड़ा

महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजस्थान 22वें पायदान पर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह सच सामने आया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश उन राज्यों की सूची में शुमार है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं।

यह अध्ययन लिंगभेद सूचकांक के जरिए गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों तथा महिला सुरक्षा व संरक्षण जैसे मानकों के आधार पर किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट भी इस सच्चाई को उजागर करती है। इसके अनुसार महिला अत्याचारों के मामले में राजस्थान देश के सबसे खराब चार राज्यों में शामिल है।

(दै.भा., 03.11.17)

बीमारियों की बड़ी वजह है कुपोषण

प्रदेश में होने वाली बीमारियों के पीछे सबसे बड़ी वजह कुपोषण है। करीब 20 फीसदी मौतें कुपोषण से होने वाली बीमारियों से हो रही है। गौरतलब यह है कि वर्ष 1990 में भी कुपोषण बीमारियों का मुख्य कारण था और 26 साल बाद भी स्थिति यही है। महिलाएं और बच्चे इससे होने वाली बीमारियों से ज्यादा प्रभावित हैं। कुपोषण के मामले में केवल बिहार हमसे आगे है।

हाल ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा देश की सेहत की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में पहली बार राज्यों को भी शामिल किया गया। रिपोर्ट से राजस्थान के सेहत की पड़ताल करने पर यह सच्चाई सामने आई, जो बेहद चिंताजनक है। *(दै.भा., 21.11.17)*

मातृ-शिशु मृत्यु दर अब भी खराब

प्रदेश के पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के जीवन स्तर में भले ही थोड़ा सुधार आया हो, लेकिन मातृ-शिशु मृत्यु दर के मामले में राजस्थान की स्थिति अब भी खराब है। यह देश में निचले पांच राज्यों में शामिल है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के ताजा नतीजों और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के परिणाम के मुताबिक प्रदेश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट तो आ रही है लेकिन राजस्थान अभी भी काफी पीछे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन स्तर में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अभी भी आशातीत सुधार नहीं आ पाया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 44 और शहरी क्षेत्र में 31 है। महिलाओं में 18 की उम्र से कम आयु में विवाह का प्रतिशत 29.8 की गिरावट के साथ 35.4 दर्ज किया गया है।

(रा.प., 05.12.17)

नसबंदी की सजा भुगत रही महिलाएं

नागौर निवासी रतनलाल की पत्नी प्रेम की पिछले साल नसबंदी के दौरान मौत हो गई। विभाग ने रतनलाल को एक लाख रुपए का मुआवजा देकर अपनी गलती पर पर्दा डाल दिया। अब रतनलाल मजदूरी करता है और घर आकर अपने तीन बच्चों को संभालता है। यह कोई एक मामला नहीं है, पिछले दो साल में प्रदेश में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 12 महिलाओं की मौत हो गई।

इसके अलावा प्रदेश में हजारों महिलाएं हर साल नसबंदी फेल होने की भी सजा भुगत रही हैं। प्रदेश में हर साल 2000 से भी ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन फेल हो रहे हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार को हर साल औसतन 8 से 10 करोड़ रुपए नसबंदी फेल होने की वजह से मुआवजा चुकाना पड़ रहा है।

(दै.भा., 08.10.17)

टीकाकरण में शामिल नहीं कई टीके

चिकनपॉक्स, टायफाइड, निमोनिया, हेपेटाइटिस-ए और एमएमआर (मॉम्स मीजल्स रोबेला) वो बीमारियां हैं जो बच्चों में सामान्य है। इसके बावजूद इन बीमारियों के टीके सरकारी टीकाकरण अभियान में ही शामिल नहीं है। इसका सीधा फायदा जहां निजी अस्पताल उठा रहे हैं, वहीं खामियाजा परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।

निजी अस्पताल इन बीमारियों के नाम पर महंगे टीके बच्चों को लगा रहे हैं। दरअसल फर्क सरकार की पॉलिसी का है। राज्य के सरकारी अस्पताल केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर टीकाकरण अभियान चलाते हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार को लिखा भी गया है लेकिन अभी तक केन्द्र ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। *(दै.भा., 15.10.17)*

प्रदेश में नवजातों की मौत का सच...

प्रदेश में नवजात बच्चों की मौत का रूह कंपाने वाला सच सामने आया है। सरकार ने अदालत में स्वीकार किया है कि प्रदेश में पिछले छह महीने में 15 हजार से भी ज्यादा नवजातों की मौत हुई है। डेढ़ हजार से ज्यादा नवजात तो अकेले अक्टूबर महीने में ही मौत के ग्रास बने हैं।

राजस्थान पत्रिका में छपी खबर पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका की जस्टिस संगीत लोढ़ा व जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार ने ये भयावह आंकड़े पेश किए हैं।

गौरतलब यह भी है कि गलत आंकड़े पेश करने वाली सरकार प्रसव का सही आंकड़ा तक नहीं जुटा पा रही है। राज्य में हर साल 3 लाख प्रसव ऐसे होते हैं जिनका सरकार को पता ही नहीं होता, तो जच्चा-बच्चा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

(रा.प., 30.11.17, 12.12.17)

एक भी महिला समूह डिफाल्टर नहीं

राजस्थान में 18 जिलों के 4 लाख 80 हजार ग्रामीण महिलाओं ने समूह में एकत्र होकर खुद को सशक्त करने के साथ ही परिवार और गांव को आर्थिक मजबूती दी है। पिछले एक साल में 9826 महिला समूहों को ऋण दिया गया। गर्व की बात यह है कि इन समूहों में से एक भी समूह डिफाल्टर नहीं है।

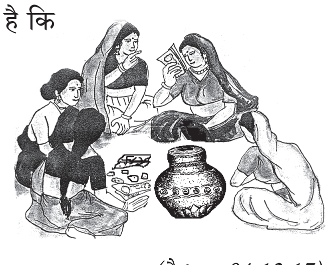

इन समूहों को जितना ऋण बांटा जा रहा है उसकी 100 फीसदी राशि समय पर वापस जमा हो रही है। साथ ही समूह की करीब 74 फीसदी महिलाओं की आमदनी में इजाफा हुआ है। ऐसे में महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने में स्वयं सहायता समूह खासे मददगार साबित हो रहे हैं। *(दै.भा., 04.12.17)*

सड़क सुरक्षा

'कट्स' ने दिए मोटर वाहन अधिनियम हेतु सुझाव

वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक-2017 को राज्यसभा में पास करवाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में राज्यसभा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम पर गठित चयन समिति के आमन्त्रण पर 'कट्स' इंटरनेशनल ने संसद भवन में आयोजित बैठक में संशोधन अधिनियम को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनमें ड्रिंक एण्ड ड्राइव, सैफ्टी हेलमेट नियम, शैक्षिक अनिवार्यता आदि से सम्बन्धित प्रमुख थे।

बैठक में 'कट्स' की तरफ से जॉर्ज चेरियन व मधुसूदन शर्मा ने भाग लिया एवं सुझाव प्रस्तुत किए। चयन समिति के अध्यक्ष विनय.पी. सहस्त्रबुद्धे ने दिए गए सुझावों की प्रशंसा की एवं 'कट्स' द्वारा सड़क सुरक्षा पर किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

जन स्वास्थ्य

मरीजों तक पहुंच रही नकली दवाएं

प्रदेश में नकली दवाओं का कारोबार फल-फूल रहा है। पिछले दस सालों में ही दवाओं के 1,305 सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं। नकली दवाओं की जांच के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन तक नहीं हैं। नकली दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नकली दवा बेचने वालों के हौंसले भी बुलन्द हैं।

नकली दवा के मामले में सिर्फ एक को सजा हो पाई है। दवाओं के 5 हजार से अधिक मामले लैब में जांच के लिए पड़े हुए हैं। पेंडेंसी का आलम यह है कि औषधि नियंत्रक विभाग ने जिस दवा का सैंपल लिया है, जब तक उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, तब तक वह दवा हजारों मरीजों में बंट चुकी होती है।

गौरतलब यह है कि सरकारी स्तर पर एकमात्र लैब जयपुर में स्थापित है। अकेली लैब होने के कारण पूरे प्रदेश से लिए दवा के सैंपलों की जांच का जिम्मा यह लैब ही उठा रही है। स्टॉफ और संसाधनों की कमी के चलते यहां 5,390 सैंपल जांच के लिए पेंडिंग पड़े हैं।

पिछले दस सालों में विभाग ने 23,484 सैंपलों की जांच की, इसमें से 1,305 सैंपल फेल हो गए। कई दवाओं की जांच में दवा का शून्य घटक तक पाया गया। सरकार ने तीन जिलों में भी लैब स्थापित करने की कवायद शुरू की है, ताकि पेंडेंसी कम हो सके। इनको बनाने में सरकार 15 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस समस्या का निपटारा हो सकेगा। *(दै.भा. 31.10.17)*

पर्यावरण

वायु प्रदूषण से जिंदगियां दांव पर

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर करोड़ों रुपए फूंके जाने के बावजूद राज्य में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण की वजह से राजस्थान में पिछले चार वर्ष के दौरान 344 लोग सांस की बिमारी के चलते जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब सवा करोड़ लोग किसी न किसी तरह से इसकी चपेट में आए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है।

गौरतलब है, अभी हाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मॉग की समस्या को लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान को भी प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने और इसके लिए जरूरी उपाय करने को कहा था।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दो साल से प्रदूषण मंडल को एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत एक भी पैसा जारी नहीं किया है। इसके चलते बोर्ड की 3 पीएम 2.5 सैम्पलर मशीनें तक खराब पड़ी है। जिनमें जोधपुर की एक और जयपुर की दो मशानें शामिल हैं। वहीं, राज्य सरकार की लचर हालत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रदेश में पॉल्युशन को लेकर कोई एक्शन प्लान तक नहीं है। *(रा.प. एवं दै.भा., 17.12.17)*

महिलाएं जागरूक होकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ लें...

'कट्स' द्वारा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के तहत 18 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए रेखा व्यास, भाजपा जिलाध्यक्ष (महिला मोर्चा) ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं जागरूक हों और बैंकिग सुविधाओं का लाभ लें साथ ही पात्र लोगों का श्रमिक कार्ड बनवाने में उनकी मदद करें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राशमी के उपखण्ड अधिकारी पंकज शर्मा ने कहा कि ग्रामीण महिला उपभोक्ता बैंकिंग योजनाओं की ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले और अन्य महिलाओं तक उन योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी करें, ताकि गांव की महिलाएं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम में बीआरकेजीबी बैंक के शाखा प्रबंधक तिवाड़ी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में बैंकिंग सेवाओं और लाभप्रद योजनाओं की जानकारी देते हुए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। बैंक ऑफ बड़ौदा भीलवाड़ा शाखा के एफ.एल.सी. कॉर्डिनेटर पी.आर.नाहर ने मुख्यवक्ता के रूप में संबोधित करते हुए सूक्ष्म बीमा योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में 'कट्स' जयपुर के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने परियोजना के उद्देश्यों और प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सूचना व परामर्श समिति के भगवान लाल शर्मा व गोवर्धन लाल शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन 'कट्स' के मदन गिरी गोस्वामी ने किया।

उपभोक्ता फैसले

ब्रेकफास्ट में निकला कीड़ा, एअर इंडिया देगी जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एम.के. मित्तल की पत्नी डॉ. नीलम मित्तल ने उपभोक्ता मंच, इलाहाबाद में एअर इंडिया के खिलाफ परिवाद दायर किया। उन्होंने मंच को बताया कि वह 8 जून, 2008 को एअर इंडिया के हवाई जहाज द्वारा कोलकाता से अंडमान निकोबार प्रान्त की राजधानी पोर्ट ब्लेयर गई थीं। एअर इंडिया अपने यात्री को रास्ते में खाना, नाश्ता और पानी देता है। उसका चार्ज टिकट में शामिल रहता है। यात्रा के दौरान उन्हें नाश्ते के रूप में दक्षिण भारतीय व्यंजन दिया गया। इस नाश्ते में एक कीड़ा निकला। इस पर उन्होंने ऐतराज जताया। मांगने के बाद भी उन्हें दोबारा खाने को कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने एअर इंडिया को सेवा का दोषी माना और आदेश दिया कि वह डॉ. नीलम मित्तल को हुई मानसिक पीड़ा की एवज में एक लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करें। साथ ही मुकदमा खर्च के पांच हजार रुपए भी अलग से दिए जाएं। जुर्माना राशि दो माह के अंदर नहीं देने पर आठ प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त देना होगा। *(दै.भा., 29.10.17)*

होटल को महंगा पड़ गया चाय पर टैक्स काटना

राजकोट में रैयाधार क्षेत्र निवासी मोहितराज राठौड़ ने होटल न्यू अंकुर के खिलाफ उपभोक्ता मंच में मामला दर्ज कराया। अपने परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि वह कार चालक है। वह कार से 4 जुलाई को राजकोट से जूनागढ़ जा रहे थे। इस दौरान वह हाईवे स्थित होटल न्यू अंकुर पर चाय पीने के लिए रुके और दो कप चाय का आर्डर दिया। होटल ने दो कप चाय के 50 रुपए वसूले, जिसमें 7 रुपए 63 पैसे टैक्स (जीएसटी) के रूप में शामिल किए गए थे। उन्होंने चाय पर लगाए गए इस टैक्स पर आपत्ति जताई और होटल संचालक से स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन होटल संचालक की ओर से उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः हारकर उन्होंने मंच में मामला दर्ज कराया है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने चाय पर जीएसटी टैक्स वसूलने को सेवा दोष करार दिया और होटल न्यू अंकुर के संचालक को निर्देश दिया कि वह टैक्स की रकम छह फीसदी ब्याज के साथ उपभोक्ता मोहितराज राठौड़ को वापस करे। इतना ही नहीं, मंच ने होटल संचालक को उन्हें मानसिक प्रताड़ना व परिवाद खर्च के एवज में 1500 रुपए भी अदा करने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 27.10.17)*

बैंकिंग शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम

किसी भी बैंक में दस वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय बैंक खातों से धन निकासी हो सकती है। ग्राहकों को अपने बैंक अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए बैंकिंग कार्यों का निष्पादन सही समय पर करना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 'कट्स' एवं सहयोगी संस्था ज्योतिबा फुले शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय करौली में आयोजित जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक मैनेजर वी.सी.गुप्ता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बैंकों में उपभोक्ताओं के लिए कई योजनाएं होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में वे बैंक द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। कार्यक्रम में दिशा ट्रस्ट के मुनीष पी. कोठारी ने बैंकिंग कार्य प्रणाली, एटीएम, डेबिट कार्ड, पॉश मशीन आदि की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग की तकनीकी जानकारी देते हुए बैंकिंग लोकपाल, भीम एप्स, शिकायत प्रक्रिया और भ्रान्तिपूर्ण विज्ञापनों आदि के बारे में भी बताया।

कार्यशाला में करौली आईडीबीआई बैंक के सहायक मैनेजर विक्रम सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर बीरबल मीना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के मैनेजर अशोक मंगल आदि ने भी उपस्थित संभागियों को संबोधित करते हुए अटल पेंशन योजना, केवाईसी, इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, खाते के उत्तराधिकारी, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंकिंग चार्जेज आदि की जानकारी दी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने बैंक उपभोक्ताओं के संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संस्था आरबीआई के साथ मिल कर बैंक उपभोक्ताओं के मुद्दों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बैंक ग्राहकों से उचित व्यवहार करें, पारदर्शिता रखें, ईमानदारी से लेन-देन करें तथा शिकायतों का समय पर समाधान करें। कार्यक्रम में स्थानीय बैंकों के अधिकारी, मीडिया व उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि एवं आमजन सहित करीब 70 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।